

**ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025**

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत होली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती पूजा देवी	1.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री हरीश कुमार	01.04.2024 से 01.12.2024
2.	श्री अजीत कुमार	02.12.2024 से 31.03. 2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्र० सं०	गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना।	6.1	07.12
2.	पंचायत राजस्व, (गृहकर) मोबाईल टावर व दूकान किराया की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1,7.2, 7.3	1.81
3.	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	8.1	1.53
4.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के बिना अनियमित भुगतान करने बारे।	8.2	6.58
5.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.31
6.	आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	8.4	0.13
7.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	8.5	2.24

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या -02 दिनांक 24-04-2025 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसके संदर्भ में सचिव द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया कि केवल कुछ ही अंकेक्षण पैरों का निपटान किया गया है। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	8 क	अंशत निर्णीत	24475 की वसूली कर ली गई है।
2.	9	अनिर्णीत	-
3.	10	अनिर्णीत	-
4.	13 (क से ज)	अनिर्णीत	-
5.	14	अनिर्णीत	-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	1-3	निर्णीत	-कार्रवाई देख ली गई है
2.	4	--	-वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
3.	4.2	निर्णीत	-कार्रवाई देख ली गई है
4.	5.1	निर्णीत	- कार्रवाई देख ली गई है
5.	5.2	निर्णीत	- वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
6.	6.1	अर्धनिर्णीत	- कार्रवाई देख ली गई है
7.	6.2	अनिर्णीत	-
8	7.1	अनिर्णीत	-
9	7.2	अनिर्णीत	-
10	7.3	अनिर्णीत	-
11	7.4	अनिर्णीत	-
12	7.5	अनिर्णीत	-
13	8.1	निर्णीत	--कार्रवाई देख ली गई है
14	8.2	अनिर्णीत	-

15	8.3	अनिर्णीत	-
16	8.4	अनिर्णीत	-
17	9.1	अनिर्णीत	-
18	9.2	निर्णीत	-
19.	9.3	अनिर्णीत	-
20.	9.4	अनिर्णीत	-
21.	9.5	अनिर्णीत	-
22.	10.1	निर्णीत	-पुन प्रारूपित
23.	10.2	अनिर्णीत	-कार्रवाई देख ली गई है
24.	10.3	निर्णीत	-कार्रवाई देख ली गई है
26	10.4	निर्णीत	पुन प्रारूपित

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत होली, विकास खंड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-04-2024 से 01-05-2025 तक ग्राम पंचायत होली के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	04/2024	09 /2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अध्याचना संख्या -12 दिनांक 02-05-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत होली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4. (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत होली के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	2751020	904915	3655935	856615	2799320

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	1173086	7936031	8204202	7491696	712506

कुल योग (1 + 2) = ₹2799320 + ₹712506 = ₹3511826

(ब) ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2025 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	मद	राशि 31-03-2025
1.	18610101695,	HPSCB HOLI	5TH SFC /SF	2798055
2.	18610105266,	HPSCB HOLI	LADP	347027
3.	18610108220,	HPSCB HOLI	PMAGYS	365479
			Cash in hand	1265
Total				3511826

अन्तर (ब-अ) ₹3511826-₹ 3511826= ₹ 0

4.2 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इ- ग्राम स्वराज के अतर्गत संधारित रोकड़ बहियाँ मद/ शीर्ष अनुसार संधारित न करके एक ही शीर्ष / मद में संधारित की जा रही थी जिस कारण उक्त शीर्ष /मद के प्रारम्भिक शेष व अन्त शेष का पता लगाना मुश्किल था तथा किस मद / शीर्ष में कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई व खर्च हुई अंकेक्षण में पता नहीं लग सका। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-11 दिनांक 01-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को मद / शीर्ष अनुसार तैयार किया जाएगा।

अतः भविष्य में उक्त मदों/शीर्षों को अलग अलग दर्शाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट व Sfc तथा अन्य प्राप्त अनुदानों को भी पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 01-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक :- 01.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹7.12 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा “परिशिष्ट - 3” पर अनुदानों से सम्बंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ 712506.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 01.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत होली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि “भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।”

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 01-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त

न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।
अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

6.3 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 05 दिनांक 29-04-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.90 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बंधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा ग्रह कर की वसूली नियमानुसार नहीं की जा रही थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹90685/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2025 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2024-25	99635	657	25	16425	116060	25375	90685

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 29-04-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर की कम्पनी से बकाया शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹0.30 लाख का बकाया शेष :-

प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार था। पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार

कोई भी मोबाईल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होता था ।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाईल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नहीं चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती थी ।

ग्राम पंचायत होली विकास खंड भरमौर जिला चम्बा के अभिलेखों की जांच एवम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ग्राम पंचायत द्वारा बकाया स्थापना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क अभी तक नहीं वसूला गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है :-

Years	Op.Balance	No. of Tower	Rate	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2024-25	30000	1	0	0	30000	0	30000

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त करना शेष था । उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वार्षिक शुल्क लेने के लिए मोबाईल कम्पनी को लिखित मांग पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी करना चाहिए था परन्तु अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल कम्पनी को शुल्क लेने के लिए कोई मांग पत्र / नोटिस जारी नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है । इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था । अतः मोबाईल टावर फीस नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है की पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवम कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं थी जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या -03 दिनांक 29-04-2025 के अवगत करवाया गया था जिसका कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया । अतः उक्त की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7.3 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.61 का वसूली हेतु शेष पाया जाना एवं दुकानों के आवंटन में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु निम्न कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी कानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

- 1) उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)
- 2) खंड विकास अधिकारी (सदस्य)
- 3) प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)
- 4) पंचायत निरीक्षक (सदस्य)
- 5) पंचायत सचिव/ सहायक (सदस्य)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध करेगी एवं उसमें निम्न शर्तें भी निर्धारित करेगी:-

- 1) सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो।
- 2) किराये में वृद्धि का प्रावधान **किराया नियंत्रण अधिनियम 1987** के अनुरूप रखा जाये।
- 3) यदि कोई किरायेदार किराया नहीं देता है अथवा परिसर को नुकसान पहुंचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाये।
- 4) किरायेदार को परिसर को किसी अन्य को किराये पर देने (Subletting) का अधिकार न हो।
- 5) किरायेदार परिसर में किसी भी उपयोग परिवर्तन/अतिक्रमण/निर्माण इत्यादि हेतु अधिकृत नहीं हो।
- 6) सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाये तथा परिसरों/भवनों को खुली बोली से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 7) व्यावसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा ही की जाये।

किन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि; ग्राम पंचायत द्वारा 05 दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था।

Shop rent report

PERIOD 01.04.2024 TO 31.03.2025

Financial Year	Outstanding Amount	No of shop	Rent of shop	Demand During the year	Total	Collection During the year	Closing Balances
2024-25	47400	5	250/1200	26400	73800	12000	61800

(ख) किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि: पंचायत द्वारा उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की जा रही है एवं विविध अनियमिततायें की जा रही है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान) का अनुबंध नहीं किया गया है।
2. अधिकतर दुकानों का किराया नहीं वसूला जा रहा है।
3. काफी समय से कोई भी किराया बढ़ोतरी नहीं की गई है।
4. पंचायत की सम्पत्ति को पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेठी का गठन नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 3 दिनांक 29-04-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सचिव, द्वारा सूचित किया कि " बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जाएगी एवं पंचायत द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।"

उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रति उदासीनता का द्योतक है; जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है एवं भविष्य में किसी वैधानिक कठिनाई का समाना करना पड़ सकता है। अतः दुकानों के किराये की बकाया राशि की शीघ्रतिशीघ्र वसूली करके एवं दुकानों के आबंटन में नियमानुसार कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 व्यय

8.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹1.53 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, (Tenders), कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत होली द्वारा राशि ₹152645/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

क्र० सं०	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	SACHIDANAND COMPUTER SOLUTION MATOUR KANGRA	SF	01/2.04.2024	OFFICE EXP	28800
2	JAGDISH CHAND SONS VPO HOLI	SF	03,04/06.04.24	OFFICE EXP	12365
3	MANI RAM HARDWARE STORE	SF	65/27.11.24	STEEL PURCHASE	81480
4	25/13.06.24	SF	SUJAN SINGH VILL BANOON HOLI	STONE	30000
				Total	152645

अंकेक्षण अध्याचना संख्या -05 दिनांक 29-04-2025 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत होली के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹6.58 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फॉर्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट - '4' द्वारा राशि ₹658455 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹658455 का अनियमित भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: -06 दिनांक 19.04.25 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त भुगतान

को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.31 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान तथा सेवा पर 18 % GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹ ₹658455/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट " 4 " में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान/साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹31354.9 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 29-04-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत

से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

8.4 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर 0.13 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चयनित माह 09/24 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट " 04"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹658455 का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹13169 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है। इस बारे में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या -11 दिनांक 29-04-2025 के संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया जोकि कर्मचारी की उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त जीएसटी टीडीएस की कटौती की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8.5 सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा । किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा । अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी ।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹224048.0 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी ।

SR. No	Voucher no./date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Amount
1	65/27.11.24	SF	MANI RAM HARDWARE STORE	STEEL PURCHASE	81480
2	25/13.06.24	SF	SUJAN SINGH VILL BANOON HOLI	STONE	30000
3	36/06.08.24	SF	ANIL KUMAR VILL TIARI PO HOLI	SAND ,AGG	18848
4	02/03.04.24	LADP	SUJAN SINGH VILL BANOON HOLI	SAND	93720
				TOTAL	224048

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या -08 दिनांक 29-04-2025 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया । इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा ।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9 विविध अनियमिततायें

9.1 मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत होली के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मस्टर रोल के साथ साथ पंचायत द्वारा समस्त बिल/ वाउचर का भुगतान भी बिना संयुक्त हस्ताक्षर के किया जा रहा था तथा उक्त भुगतानों को पंचायत द्वारा बिना पारित किये किया गया था जोकि अनुचित है। तथा किये जा रहे भुगतानों पर पारित प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं थे जोकि अनुचित है।

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 व 10 दिनांक 29.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया

अतः उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.1 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थायी एवं अस्थायी भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO व वेंडर लिस्ट व BPL रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर		

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11, दिनांक 29.04.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत, सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान, इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11, दिनांक :-29-04-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

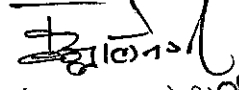
10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
12. **निष्कर्ष:-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।


(कृष्ण लाल नेगी) 08/7/25
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009 ~

दूरभाष-0177-2626670

का०/ख०

09 JUL 2025

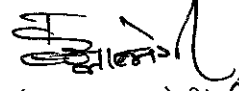
4303-4307

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)68/2021 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत होली, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

09 JUL 2025


(कृष्ण लाल नेगी) 08.7.25
सहायक निदेशक

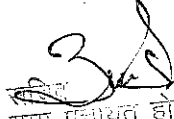
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009 ~

का०/ख०

24/12/2024-1 पंरा संख्या 4(37) 1 जे लंदरने

Financial Position of Own Sources in r/o			" GP HOLI"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	2751020	904915	3655935	856615	2799320


ग्राम पंचायत होली
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)


प्रधान
ग्राम पंचायत होली
विकास खण्ड भरमौर

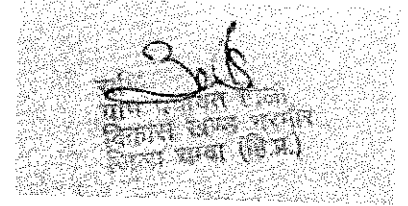
परिशिष्ट -2 पैरा संख्या 4(क) 2 के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Holi D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	1173086	7031116	8204202	7491696	712506



Jr. Auditor
H.P. State Audit Department
Audit Circle Chamba

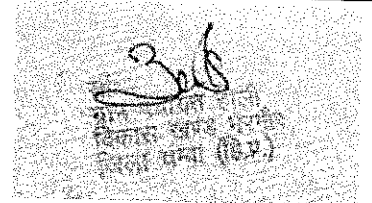


परिशिष्ट -3 पैरा संख्या 6.1 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP HOLI"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP	Year Ended	2024-25
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PMAGYS	512594				
2	LADP	660492	446085	958679	593200	365479
3	MNREGA	0	414797	1075289	728262	347027
	Total	1173086	6170234	6170234	6170234	0
	Balane As Per Cash Book		7031116	8204202	7491696	712506
1	Balance on 31.03.2025	(Own Source)/SFC				
2	Balance on 31.03.2025	PMAGYS				2799320
3	Balance on 31.03.2025	LADP				365479
4	Balance on 31.03.2025	MNREGA				347027
						0
	Balance as per Bank			Total		3511826
	A/c No	Branch	Head			
1	18610101695,	HPSCB HOLI	5TH SFC /SF			
2	18610105266,	HPSCB HOLI	LADP			2798055
3	18610108220,	HPSCB HOLI	PMAGYS			347027
		Cash In Hand				365479
	Total					1265
						3511826
				Difference		0
	1. Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position					

(Signature)

उपस्थित
जिला विकास अधिकारी
जिला चम्बा (H.P.)



STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE, SAND, AGG, PURCHASE FROM VENDOR WITHOUT W/X FORM AND GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT

SR.	NAME OF VENDEE/	GRANTS/	BILL NO./DATE OF PAYMENT	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED	TDS ON GST	
NO.	SUPPLIER	HEAD	BILL NO	DATE OF PAYM	MATERIAL	PAID			
1	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	19	10-09-2024	STONE	23693	22564.8	1128.2	473.86
2	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	21	10-09-2024	STONE	16514	15727.6	786.4	330.28
3	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	22	10-09-2024	STONE	11129	10599	530	222.58
4	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	23	10-09-2024	STONE	13684	13032.4	651.6	273.68
5	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	20	10-02-2024	STONE	21600	20571.4	1028.6	432
6	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	11	10-02-2024	STONE	4750	4523.8	226.2	95
7	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	9	10-02-2024	STONE	21504	20480	1024	430.08
8	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	7	10-02-2024	STONE	21504	20480	1024	430.08
9	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	89	10-02-2024	STONE	28728	27360	1368	574.56
10	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	87	10-02-2024	STONE	11840	11276.2	563.8	236.8
11	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	88	10-02-2024	STONE	4327	4121	206	86.54
12	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	18	10-02-2024	STONE	11700	11142.9	557.1	234
13	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	8	10-02-2024	STONE	8019	7637.1	381.9	160.38
14	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	70	10-02-2024	STONE	8750	8333.3	416.7	175
15	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	13	10-02-2024	STONE	11664	11108.6	555.4	233.28
16	ANIL KUMAR GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	27	12-10-2024	SAND,AGGRIGATE	79920	76114.3	3805.7	1598.4
17	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	17	12-10-2024	SAND,AGGRIGATE	100633	95841	4792	2012.66
18	OKHU RAM GOVT CONTRACTOR HOLI	MGNREGA	16	12-10-2024	SAND,AGGRIGATE	66825	63642.9	3182.1	1336.5
19	M/S SUJAN SINGH GOVT CONTRACTOR BANOON HOLI	MGNREGA	76	27-08-2024	SAND,AGGRIGATE	36542	34801.9	1740.1	730.84
20	M/S SUJAN SINGH GOVT CONTRACTOR BANOON HOLI	MGNREGA	75	27-08-2024	SAND,AGGRIGATE	12561	11962.9	598.1	251.22
21	SUJAN SINGH VILL BANOON HOLI	SF		25/13.06.24	STONE	30000	28571.4	1428.6	600
22	ANIL KUMAR VILL TIARI PO HOLI	SF		36/06.08.24	SAND ,AGG	18848	17950.5	897.5	376.96
23	SUJAN SINGH VILL BANOON HOLI	LADP		02/03.04.24	SAND	93720	89257.1	4462.9	1874.4
Total						658455	627100.1	31354.9	13169.1

26

5